

विमुद्रीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव : एक अध्ययन

Sabiha Anjum¹ and Dr. Aslam Sayeed²

Research Scholar, Department of Commerce¹

Professor and Head, Department of Commerce²

AKS University, Satna, M.P., India

सारांश –

8 नवंबर 2016 को रात 8 बजे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र के संबोधन में अप्रत्याशित रूप से इस बात की घोषणा की गई कि मध्य रात्रि से उच्च मूल्य वर्ग के ₹ 500 एवं ₹ 1000 के नोट लीगल टेंडर (वैध मुद्रा) नहीं रहेंगे अर्थात् सीमित अवधि में सीमित सेवाओं के साथ इसकी वैधता समाप्त हो जाएगी।

विमुद्रीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सरकार किसी भी सीरीज एवं मूल्यवर्ग की मुद्राओं को अवैध घोषित कर चलन से बाहर कर देती है। सामान्यतः इस प्रक्रिया में प्रचलित पुरानी मुद्रा की जगह नई मुद्राएँ लाई जाती हैं। ऐसा कई बार काले धन पर अंकुश एवं जाली मुद्रा पर नियंत्रण हेतु होता है।

सरकार की मानें तो काले धन को समाप्त करना विमुद्रीकरण का प्राथमिक लक्ष्य था हालाँकि कई लोगों ने भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा जारी आँकड़ों के आधार पर नोटबंदी के इस उद्देश्य पर प्रश्नचिह्न लगाया है।

काला धन असल में वह आय है जिसे कर अधिकारियों से छुपाने का प्रयास किया जाता है यानी इस प्रकार की नकदी का देश की बैंकिंग प्रणाली में कोई हिसाब नहीं होता है और न ही इस पर किसी प्रकार का कर दिया जाता है।

वर्ष 2018 में भारतीय रिज़र्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट में दर्शाया गया था कि विमुद्रीकरण के दौरान अवैध घोषित किये गए कुल नोटों का तकरीबन 99-3 प्रतिशत यानी लगभग पूरा हिस्सा बैंकों के पास वापस आ गया था। आँकड़ों के मुताबिक अमान्य घोषित किये गए 15-41 लाख करोड़ रुपए में से 15-31 लाख करोड़ रुपए के नोट वापस आ गए थे। फरवरी 2019 में तत्कालीन वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने संसद को बताया था कि विमुद्रीकरण समेत सभी प्रकार के काले धन को समाप्त करने के लिये उठाए गए विभिन्न उपायों के कारण 1-3 लाख करोड़ रुपए का काला धन बरामद किया गया था, जबकि सरकार ने विमुद्रीकरण की घोषणा करते हुए इस संबंध में तकरीबन 3-4 लाख करोड़ रुपए बरामद करने की बात कही थी। अतः आँकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि विमुद्रीकरण यानी नोटबंदी भारतीय अर्थव्यवस्था से काले धन की समस्या को समाप्त करने में कुछ हद तक विफल रही है।

मुख्य शब्द :- विमुद्रीकरण, भारतीय, अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था आदि।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. योजना पत्रिका जनवरी 2019
2. कुरुक्षेत्र पत्रिका मार्च 2018
3. दैनिक समाचार पत्र